5000 कर्मचारियों को पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने लगाया है उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगा प्रभावित इलाकों की सफाई के काम में। हालांकि अभी सफाई कर्मचारी उन इलाकों में नहीं जा रहे हैं, जहां ज्यादा खतरा है।

जस्टिस मुरलीधर के तबादले पर संग्राम

सियासत ▶ कांग्रेस ने कहा – दिल्ली दंगों में भाजपा नेताओं को बचाने के लिए रातोंरात हुआ ट्रांसफर

कानून मंत्री ने कहा– सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 12 फरवरी को की थी अनुशंसा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के जज मुरलीधर का पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में तबादला किए जाने पर जबर्दस्त सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस ने न्यायपालिका पर दबाव डालने और भाजपा की बदले की कार्रवाई करार दिया। वहीं, केंद्र सरकार ने कांग्रेस के काल में न्यायपालिका के साथ व्यवहार की याद दिलाते हुए स्पष्ट किया कि तबादले की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट से ही आई थी। प्रक्रिया के अनुसार जस्टिस मुरलीधर से भी सहमति ली गई थी। लेकिन परिवारवाद से ग्रसित कांग्रेस जज के रुटीन ट्रांसफर का राजनीतिकरण कर रही है।

दिल्ली में दंगे भड़काने के लिए भाजपा नेताओं कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ भड़काऊ भाषणों पर एफआइआर दर्ज नहीं करने को लेकर जस्टिस मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को जमकर लताड़ लगाई थी। साथ ही गुरुवार तक इनके खिलाफ एफआइआर दर्ज करने पर विचार करने को कहा था। बुधवार देर रात ही कानून मंत्रालय ने जस्टिस मुरलीधर का तत्काल प्रभाव से तबादला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी। तत्काल कांग्रेस ने इसे लपक लिया और चौतरफा हमला बोल दिया। पार्टी ने कहा कि भाजपा नेताओं को बचाने के लिए ही जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर किया गया है।

कांग्रेस के आरोपों का जवाब खुद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया। उन्होंने कहा कि तबादले का राजनीतिकरण कर कांग्रेस न्यायपालिका के सम्मान को ठेस पहुंचा रही है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की ओर से 12 फरवरी को अनुशंसा की गई थी। कोलेजियम की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते है। इसमें पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। तबादले को लेकर जस्टिस मुरलीधर की सहमति भी ली गई थी। रविशंकर ने कहा कि न्यायपालिका पर दबाव बनाने की लत कांग्रेस की रही है। इतिहास गवाह है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीशों को नजरअंदाज कर कनिष्ठ न्यायाधीश को गद्दी पर बिठाया गया था। जस्टिस लोया की मौत के मामले पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला दे चुका है और राहुल गांधी क्या अदालत से ऊपर हैं? कानून मंत्री ने कहा कि सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आदर करती है।

जस्टिस मुरलीधर की फाइल फोटो। ट्विटर

- अनुशंसा से पहले जस्टिस मुरलीधर की भी ली गई थी सहमति
- दंगों में भाजपा नेताओं पर एफआइआर दर्ज नहीं करने को लेकर जस्टिस मुरलीधर ने पुलिस को लगाई थी लताड़

प्रियंका की अगुआई में घेराबंदी : उससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हमले की शुरुआत करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार के दौर में आधी रात को जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर हैरत वाला भले न हो मगर निश्चित रूप से यह दुखद और शर्मनाक है। न्याय को दबाने और लोगों के विश्वास को तोड़ने का यह प्रयास निंदनीय है। राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए जस्टिस लोया को याद किया और कहा कि उनका तबादला नहीं हुआ था। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि तबादले ने भाजपा के प्रतिशोध और न्यायपालिका पर दबाव बनाने की रणनीति का पर्दाफाश कर दिया है।

सुरजेवाला ने कहा कि न्यायपालिका पर अनुचित दबाव बनाने का भाजपा का इतिहास रहा है। गोपाल सुब्रमण्यम को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की कोलेजियम की सिफारिश को मोदी सरकार ने रोक दिया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ गुजरात दंगों के मामले में सुब्रमण्यम वकील रहे थे। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार गिरा कर राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को पलटने वाले जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने में लगाए गए अवरोधों की बात पुरानी नहीं हुई है। जस्टिस अकील कुरैशी की नियुक्ति में अड़चन का मामला हो या दिल्ली हाई कोर्ट की वरिष्ठ जज जस्टिस गीता मित्तल का तबादला, भाजपा सरकार ने न्यायपालिका के प्रति बदले की भावना बार-बार दिखाई है।

नेताओं के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट तलब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा मामले की विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने पक्षकार बनाकर जवाब दाखिल करने की केंद्र सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के मामले पर चार सप्ताह में केंद्र व दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।

बुधवार को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा था कि दिल्ली में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। ऐसे में उसे भी पक्षकार बनाया जाए। मुख्य पीठ ने इस दलील को स्वीकार कर लिया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता हर्ष मंदर की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता कॉलिन गोन्साल्वे ने पीठ से मांग की कि भड़काऊ भाषण देने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ तत्काल एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया जाए। इन सभी के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने कोर्ट से नजदीक की तारीख देने की मांग की।

- भड़काऊ भाषण मामले में अब 13 अप्रैल को होगी सुनवाई
- सोनिया, राहुल और प्रियंका के खिलाफ भी याचिका दायर

दिल्ली हाई कोर्ट का प्रवेश द्वार। फाइल

भड़काऊ भाषण के मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले गैर सरकारी संगठन लॉयर वाइस के अधिवक्ता चेतन शर्मा ने कहा कि यह संवेदनशील समय है और दिल्ली में शांति-व्यवस्था तत्काल बहाल होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर यह सब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के दौरान क्यों हुआ? आखिर किसने लोगों को सड़कों पर उतरने को कहा। उन सभी को गिरफ्तार किया जाए। याचिका में सोनिया, राहुल और प्रियंका के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग की गई।

सिसोदिया व अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भी याचिका : एक अन्य याचिका में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भी भड़काऊ भाषण देने के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की गई। हिंदू सेना की तरफ से याचिका में सांसद असादुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि एआइएमआइएम के नेता वारिस पठान के भड़काऊ भाषण के कारण ही दिल्ली में दंगा भड़का, जिसमें कई लोगों की जान चली गई।

हाई कोर्ट ने कहा था दोबारा 1984 जैसा दंगा नहीं होने देंगे

बुधवार को न्यायमूर्ति एस मुरलीधर व न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि वह दिल्ली में दोबारा 1984 जैसा दंगा नहीं होने देंगे। पीठ ने भड़काऊ भाषण देने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद प्रवेश वर्मा और भाजपा नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआइआर नहीं दर्ज करने पर पुलिस को फटकार लगाई थी।

दंगे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, भाजपा का पलटवार

सरकार को 'राजधर्म' निभाने का निर्देश दें राष्ट्रपति : सोनिया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस ने दिल्ली के दंगों में केंद्र पर मूकदर्शक बने रहने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से कहा है कि वे राजग सरकार को 'राजधर्म' निभाने का निर्देश दें। साथ ही गृहमंत्री अमित शाह को बर्खास्त किए जाने की मांग करते हुए कहा कि गृहमंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे जिसके चलते हिंसा में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि दिल्ली का यह दंगा बेहद चिंताजनक ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय शर्म की बात है।

सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की अगुआई में कांग्रेस के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात कर यह मांग की। मुलाकात के बाद सोनिया गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए गृहमंत्री के इस्तीफे को हटाए जाने की मांग दोहराई। राष्ट्रपति को सौंपे ज्ञापन में भी कांग्रेस ने कहा है कि स्थिति संभालने में हुई लापरवाही और विफलता के साथ अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करने के लिए गृहमंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए। राष्ट्रपति से हुई चर्चा का हवाला देते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई इलाके पिछले कुछ दिनों से हिंसा की चपेट में हैं। केंद्र तथा दिल्ली सरकार योजनाबद्ध हिंसा और प्रचंड उत्पात के हालात को संभालने में नाकाम रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस ने राष्ट्रपति से इस मामले में जरूरी दखल का अनुरोध किया है। सरकार को उसके कर्त्तव्यों और राजधर्म की याद दिलाने का सर्वोच्च दायित्व संविधान ने राष्ट्रपति को सौंपा है। कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रपति का रुख पूछे जाने सोनिया ने कहा कि राष्ट्रपति ने हमारे ज्ञापन का संज्ञान लेने की बात कही है। मनमोहन सिंह ने पत्रकारों से कहा कि हमने राष्ट्रपति से अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सरकार को राजधर्म का पालन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में दंगों को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन हालात के दौरान पूरी तरह नदारद दिखाई पड़े। इसमें दंगों की पूर्व खुफिया सूचनाओं का संज्ञान नहीं लिए जाने, ज्यादा हिंसा और उपद्रव वाले इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती नहीं किए जाने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। भाजपा नेताओं के भड़काऊ भाषणों का हवाला देते हुए कहा गया है कि सस्ते राजनीतिक लाभ के लिए नागरिकों के बीच नफरत का बीज बोया जा रहा है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में गुलाम नबी आजाद, एके एंटनी, पी. चिदंबरम, गुलाब नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, अहमद पटेल आदि भी शामिल थे।

दिल्ली हिंसा पर राष्ट्रपति से मिलीं सोनिया गांधी, अमित शाह को हटाने की मांग

सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भेंट कर गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग दोहराई। सोनिया ने कहा कि दिल्ली हिंसा के दौरान पुलिस के साथ यहां की केजरीवाल सरकार भी मूकदर्शक बनी रही। देखें वीडियो

देखें, कांग्रेस नेताओं की राष्ट्रपति से मुलाकात और मांग ऊपर छपी तस्वीर को Google Lens से स्कैन करके

वीडियो देखने के लिए

1. अपने मोबाइल पर Google Lens App डाउनलोड करके OPEN करें. Go to goo.gle/lens, or use the Google Lens App on Android/Google App on iOS
2. ऊपर छपी तस्वीर को Google Lens के साथ स्कैन करें
3. छपी तस्वीर पर आधारित विश्लेषणात्मक वीडियो देखें

गांधी परिवार ने उकसाया : जावडेकर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली हिंसा को लेकर राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष जहां भाजपा और केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहा है। वहीं भाजपा का आरोप है कि हिंसा के लिए विपक्ष और खासतौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे कांग्रेस नेता जिम्मेदार हैं जो दो महीने से सीएए के खिलाफ बारूद भरने का काम कर रहे थे। यह हिंसा दो दिन की नहीं है बल्कि दो महीने से इसे सुलगाया जा रहा था और लोगों को भड़काया जा रहा था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी कठघरे में खड़ा किया और कहा कि वह स्थिति सामान्य करने के बजाय मारे गए लोगों के धर्म बता रहे हैं। यह ओछी राजनीति है।

कांग्रेस नेता सड़क पर उतर गए हैं तो दूसरी ओर से जावडेकर ने सीधे कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने हिंसा में कांग्रेस की भूमिका बताते हुए कहा कि सरकार ने 11 दिसंबर को सीएए पास किया और तीन दिन बाद कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में रैली की। उस रैली में सोनिया गांधी ने कहा- 'यह आरपार की लड़ाई है, आपको फैसला लेना पड़ेगा कि आप इस पार हैं या उस पार।' उसी रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा- 'लाखों को बंदी बनाया जाएगा, जो नहीं लड़ेगा वह कायर कहलाएगा।' तो राहुल गांधी ने कहा-'डरो मत, कांग्रेस आपके साथ है।' जावडेकर ने कहा कि ये बयान क्या बताते हैं। जब किसी की नागरिकता नहीं जा रही थी तो ऐसे बयान देकर कांग्रेस नेता ऐसा माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह 1984 में राजीव गांधी ने 'बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है' का बयान देकर स्थिति बिगाड़ दी थी उसी तरह सोनिया का बयान भी गंभीर है। इसे सिर्फ बयान नहीं माना जा सकता है। यह सीधे तौर पर भीड़ को उकसाने के लिए कहा गया था। अब जो हिंसा दिखी उसके पीछे कांग्रेस नेता की भूमिका है। जावडेकर ने मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर आदि के भी उदाहरण दिए।

जावडेकर ने विपक्षी नेताओं और समाज के कुछ वर्गों की चुप्पी पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि गुरुवार की सुबह से दिखाया जा रहा है कि आप नेता ताहिर हुसैन के घर में असलहा था, दंगे की तैयारी थी लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुप है। हिंसा में पुलिस कांस्टेबल रतनलाल, आइबी अफसर अंकित शर्मा की शहादत होती है, डीसीपी, एसीपी जख्मी होकर अस्तपाल में भर्ती होते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां गंदी राजनीति में जुटी हैं। कांग्रेस से आप में आए अमानतुल्ला ने कहा था कि-आपको टोपी पहनने पर पाबंदी लग जाएगी। इन बयानों ने ही दरअसल हिंसा के लिए जमीन तैयार की।

स्वरा भास्कर की गिरफ्तारी की मांग उठी

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई : दिल्ली में दंगा भड़कने के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर को गिरफ्तार करने की मांग उठी है। सोशल मीडिया यूजर्स ने स्वरा के पुराने साक्षात्कार और बयानों के वीडियो साझा कर उनको गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वरा के दिए गए भड़काऊ बयान दिल्ली में हुए दंगो के मुख्य कारणों में से एक हैं। गौरतलब है कि स्वरा शुरू से ही नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हैं। और वह लगातार अलग-अलग मंचों से इसके खिलाफ आवाज उठाती आई हैं। उन्हें कई बार उनके बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया है।

दोषियों को सख्त सजा सुनिश्चित कराने में जुटे हैं अमित शाह

- गुरुवार को भी जारी रहा बैठकों का दौर, सावरकर पर कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे
- गृह मंत्री के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए गठित की दो एसआइटी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली में हिंसा में कमी आने के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जरा भी ढील बरतना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि गुरुवार को भी दिन भर गृह मंत्रालय में बैठकों का दौर जारी रहा। शाह ने दिल्ली पुलिस को हिंसा की निष्पक्ष जांच और इसके गुनहगारों को सख्त सजा सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। शाह के कड़े रुख को देखते हुए ही दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए दो विशेष जांच टीम (एसआइटी) गठित करने का एलान किया।

गुरुवार को अमित शाह को दोपहर ढाई बजे वीर सावरकर पर आयोजित एक कार्यक्रम में जाना था। यह पहले से तय था, लेकिन अमित शाह ने वहां जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। वे सुबह 11 बजे गृह मंत्रालय पहुंचे और देर रात तक लगातार दिल्ली की हालात को लेकर बैठकें करते रहे। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक और विशेष आयुक्त कानून-व्यवस्था एसएन श्रीवास्तव इन बैठकों में शामिल रहे। उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से एक-एक कदम की समीक्षा की। उन्होंने लोगों से भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। गृह मंत्री शाह ने दिल्ली पुलिस को हिंसा से जुड़े मामले में एफआइआर दर्ज करने और दोषियों की पहचान कर उन्हें कड़ी सजा सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। शाह का साफ कहना था कि हिंसा के लिए जिम्मेदार एक भी दोषी बचना नहीं चाहिए। अब तक 48 एफआइआर दर्ज किए गए हैं। पूछताछ के लिए पांच सौ से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है।

गृह मंत्रालय के मुताबिक हिंसा में कमी को देखते हुए कल धारा 144 के तहत लागू पाबंदियों में 10 घंटे की ढील देने का फैसला किया गया है।

बेरहमी से की गई थी अंकित की हत्या

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली

आइबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) में तैनात कांस्टेबल अंकित शर्मा की हत्या बहुत बेरहमी से की गई थी। गुरुवार को जीटीबी अस्पताल में उनके शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने पुलिस को प्राथमिक रिपोर्ट दे दी है। इसमें बताया गया कि अंकित के शरीर पर कई बार चाकू मारे गए हैं। इसके लिए चार से पांच चाकू इस्तेमाल किए गए। ऐसे में आशंका है कि चार से पांच लोगों ने एक साथ उन पर हमला किया था। पहचान छिपाने के लिए सिर पर कुछ ज्वलनशील पदार्थ भी डाले गए। इसके साथ उनकी आंतें भी गायब पाई गई हैं। अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ दिनों के बाद दी जाएगी।

गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर अंकित के परिजन मुजफ्फनगर, उप्र स्थित अपने गांव ले गए, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके बड़े भाई अंकुर ने बताया कि उन्हें अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। लेकिन पुलिस को एक रिपोर्ट दी गई है। इसमें बेरहमी से हत्या करने की बात सामने आई है। हम लोग शुरू से बता रहे हैं कि पार्षद ताहिर हुसैन के घर में अंकित को खींचकर ले जाया गया था। इसके बाद हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया गया। उन्होंने पुलिस से पार्षद को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।

सिर पर डाला गया ज्वलनशील पदार्थ, आंतें भी थीं गायब

दिल्ली हिंसा पर ट्रंप प्रशासन मोदी सरकार के साथ

- अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने शांति व सौहार्द बनाए रखने की अपील की
- डेमोक्रेट सैंडर्स ने दिल्ली पर ट्रंप के बयान को नेतृत्व की विफलता बताया

वाशिंगटन, एजेंसियां : दिल्ली में भड़की हिंसा पर ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर मोदी सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों का समर्थन किया है। जबकि, डेमोक्रेटिक पार्टी ने हिंसा को लेकर मोदी सरकार की आलोचना करने के साथ ही ट्रंप के बयान को नेतृत्व की विफलता करार दिया है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों के साथ हमारी संवेदना है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शांति और सौहार्द कायम रखने की अपील का समर्थन करते हैं और सभी पक्षों से शांति, संयम और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान करने का आग्रह करते हैं।

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के संभावित प्रत्याशी बर्नी सैंडर्स ने दिल्ली हिंसा पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी को नेतृत्व की विफलता करार दिया है। दो दिन की यात्रा पर आए ट्रंप ने कहा था कि दिल्ली हिंसा पर उनकी पीएम मोदी से कोई बात नहीं हुई और यह भारत का अपना मामला है। इससे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के दूसरे संभावित प्रत्याशी सीनेटर एलिजाबेथ वारेन ने भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भड़की हिंसा पर दुख जताया था।

दिल्ली हिंसा में मौतों पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जताया दुख : संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने दिल्ली हिंसा में लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने सभी लोगों से अत्यधिक संयम रखने की अपील भी की है। गुतेरस के प्रवक्ता स्टीफेन दुजारिक ने बुधवार को यहां नियमित प्रेस वार्ता में एक सवाल पर उक्त बातें कही। गुतेरस ने लोगों से हिंसा से दूर रहने की अपील भी की है। वहीं, जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त मिशेल बाचेलेट ने भी हिंसा पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से हिंसा रोकने की अपील की।

शांति स्थापना के प्रयास तेज : भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि हिंसा रोकने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। शांति बहाली के प्रयासों में सरकार के शीर्ष अधिकारी भी लगे हैं। प्रधानमंत्री ने भी सार्वजनिक रूप से लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। नेताओं से भड़काऊ बयान देने से बचने को भी कहा गया है।

खाड़ी में रहने वाले भारतीयों ने भी की शांति की अपील : संयुक्त अरब अमीरात समेत खाड़ी के देशों में रहने वाले भारतीयों ने भी दिल्ली हिंसा पर चिंता जताई है और लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है।

गांव से मजदूरी करने दिल्ली गया था ताहिर, बन गया आप पार्षद

जागरण संवाददाता, अमरोहा : दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में चर्चा में आया आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अमरोहा के गांव पौरारा का रहने वाला है। गुरुवार शाम टीवी चैनल व सोशल मीडिया पर उसके घर की छत से पेट्रोल बम, तेजाब की बोतलें बरामद होने और उपद्रव में शामिल होने की जानकारी लगी तो ग्रामीण स्तब्ध रह गए। मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है।

गांव पौरारा का रहने वाला ताहिर बीस साल पहले दिल्ली मजदूरी करने गया था। कुछ समय बाद पिता कल्लू उर्फ कल्लन सैफी भी परिवार के साथ दिल्ली में बेटे के पास पहुंच गए। गांव के पूर्व प्रधान जयपाल सिंह ने बताया कि दिल्ली के आप पार्षद ताहिर हुसैन ने कुछ वर्ष पहले गांव के अपने पुश्तैनी मकान को भी बेच दिया था। उसकी गांव में कुछ आवासीय भूमि खाली पड़ी हुई है। ताहिर साल में एक-दो बार पौरारा आता रहता था। फिलहाल करीब सालभर से वह गांव नहीं आया है। उसका एक तहेरा भाई गांव में स्कूल चलाता है।

दिल्ली में ताहिर हुसैन ने अपने कारोबार को स्थापित करने के साथ ही राजनीति में भी पकड़ बना ली थी। गांव के लक्ष्मी नारायण गिरि बताते हैं कि ताहिर हुसैन अपने पांच भाइयों में बड़ा है। गांव में कृषि भूमि व कोई अन्य रोजगार न होने पर मजदूरी करने के लिए वह परिवार सहित दिल्ली चला गया था।

दैनिक जागरण के सहयोगी मीडिया प्लेटफॉर्म विश्वास.न्यूज की पड़ताल में सामने आया सच

पुरानी तस्वीर दिल्ली हिंसा से जोड़कर वायरल

विश्वास.News
क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है
www.vishvasnews.com

जेएनएन, नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून के विरोध और पक्ष में हुए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसक झड़प के बीच सोशल मीडिया पर एक पुलिसकर्मी की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें उनके हाथों में पत्थर नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर दिल्ली पुलिस के जवान की है। विश्वास न्यूज की पड़ताल में यह दावा गलत निकला।

पड़ताल: वायरल पोस्ट में तस्वीर का इस्तेमाल किया गया इसलिए इसे गूगल रिवर्स इमेज की मदद से सर्च किया गया। रिवर्स इमेज किए जाने पर ऐसे कई लिंक्स मिले, जिसमें इस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। पड़ताल में सामने आया कि इस तस्वीर को कई तमिलभाषी यूजर्स ने कुछ सालों पहले पुलिस के हिंसक बर्ताव का दावा करते हुए शेयर किया। वेरिफाइड ट्विटर यूजर वासुकी भास्कर ने इस तस्वीर को 24 जनवरी 2017 को अपनी टाइमलाइन पर शेयर किया। फेसबुक यूजर 'जल्लीकट्टू वर्सेज पेटा' ने भी इस तस्वीर को 24 जनवरी 2017 को अपनी प्रोफाइल पर शेयर किया। फेसबुक यूजर 'निर्मलागिरी कॉलेज एसएफआइ' ने इस तस्वीर को अपनी प्रोफाइल पर 23 अगस्त 2013 को शेयर किया गया। एडवांस सर्च में यह तस्वीर और भी पुरानी डेटलाइन के साथ कई यूजर्स की प्रोफाइल पर दिखी।

वीडियो भी वायरल: सर्च में हमें यह तस्वीर 'न्यूजग्लिट्स-नेक्स्ट जनरेशन तमिल न्यूज चैनल' पर 23 जनवरी 2017 को अपलोड किए गए वीडियो के थंबनेल में भी दिखी। वीडियो के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक, जल्लीकट्टू के दौरान हुए प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद पुलिसकर्मियों को गाड़ियों में आग लगाते हुए देखा गया यानी जिस तस्वीर को दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान के पत्थरबाजी के दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। वह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 2013 से मौजूद है, जबकि दिल्ली में हिंसा की शुरुआत 23 फरवरी 2020 को हुई।

दिल्ली हिंसा से कोई वास्ता नहीं: तस्वीर में दिख रहे जवान का यूनिफॉर्म हाफ साइज का है जबकि दिल्ली पुलिस के जवान अभी भी फुल यूनिफॉर्म में हैं। पुलिस के जवान गर्मियों में हाफ यूनिफॉर्म पहनते हैं जबकि सर्दियों के दौरान फुल यूनिफॉर्म। न्यूज एजेंसी और अन्य अखबारों में प्रकाशित खबरों में इस्तेमाल की गई तस्वीरों से इसकी पुष्टि होती है।

क्या है वायरल पोस्ट में?

फेसबुक यूजर 'ओवैसी फैन क्लब' ने तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, 'आज इन्हीं की वजह से दिल्ली का माहौल खराब है।' तस्वीर को एडिट कर उस पर लिखा गया है, 'दिल्ली पुलिस खुद पत्थर मार रही है और शांतिपूर्ण तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं, उनको बदनाम किया जा रहा है।'

झूठी खबर और अफवाहों की हकीकत जानने के लिए वाट्सएप करें: 9205 270 923